विकास की गाड़ी और तेज

डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर खर्च होंगे 742 करोड़

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। डिफेंस कॉरिडोर के सभी नोड्स को और अधिक विकसित करने के लिए प्रस्तावित 742 करोड़ रुपये की राशि औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत कर दी है। इस धन से होने वाले विकास कार्यों के बाद इन कॉरिडोर में ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, विमान, आधुनिक हथियार व ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्माण को गति और लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए कई विश्वस्तरीय कंपनियों ने प्रस्ताव दिए हैं। इन्हें धरातल पर उतारने के लिए उप्र. एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के प्रस्ताव के तहत 742 करोड़ से चित्रकूट, झांसी, लखनऊ, कानपुर और अलीगढ़ नोड में चारदीवारी, सड़क, बिजली, पानी, पुलिस व फायर स्टेशन के साथ कई विकास कार्य कराए जाएंगे।

यूपीडा का प्रस्ताव स्वीकृत

झांसी नोड को 250 व चित्रकूट को मिले 125 करोड़

90 करोड़ से लखनऊ में ये काम

- चारदीवारी निर्माण : 6.10 करोड़
- प्रकाश व्यवस्था : 5.20 करोड़
- ग्राम भटगांव में जल आपूर्ति, निकासी व एसटीपी : 52 करोड़
- पुलिस और फायर स्टेशन निर्माण : 23.90 करोड़
- तीन गेटों के लिए : 1.50 करोड़

इसके लिए सबसे ज्यादा 250 करोड़ रुपये झांसी व 125 करोड़ चित्रकूट नोड में खर्च होंगे। 90 करोड़ लखनऊ, 30 करोड़ अलीगढ़ और 18 करोड़ कानपुर नोड में खर्च होंगे। शेष राशि का इस्तेमाल लखनऊ, कानपुर व अलीगढ़ में जमीन खरीदने व अवस्थापना संबंधी कार्यों में किया जाएगा।

सात शहरों में नई टाउनशिप के लिए मिलेंगे हजार करोड़

महेंद्र तिवारी

लखनऊ। गोरखपुर व बरेली सहित प्रदेश के सात शहरों में नई टाउनशिप बसाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण व नए शहर प्रोत्साहन योजना से इन शहरों के प्राधिकरणों को भूमि अधिग्रहण के लिए 1000 करोड़ रुपये देने पर सहमति बन गई है। संबंधित प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट की मंजूरी दिलाने की तैयारी है। चरणबद्ध तरीके से इन्हें 4,777.50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना को गत दिनों मंजूरी दी थी। इसमें नई टाउनशिप के विकास या पूर्व विकसित टाउनशिप के विस्तारीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि अर्जन लागत में आने वाले खर्च का 50 प्रतिशत तक सीड कैपिटल के रूप में 20 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। बाकी राशि संबंधित आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास

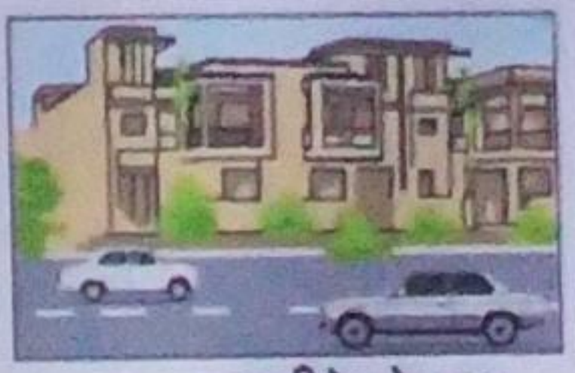

चरणबद्ध तरीके से कुल 4777 करोड़ मिलेंगे, कैबिनेट से मंजूरी की कार्यवाही शुरू

प्राधिकरण स्वयं वहन करेंगे।

योजना के अंतर्गत गोरखपुर, चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, बुलंदशहर, बरेली, झांसी व मेरठ प्राधिकरण ने आवेदन किया था। आवास विभाग की स्वीकृति एवं निगरानी समिति ने इनमें से मेरठ व कानपुर को छोड़ते हुए बाकी सात प्राधिकरणों को राशि आवंटित किए जाने की संस्तुति कर दी है। इन दोनों शहरों के प्रस्ताव कसौटी पर खरे नहीं उतरे। कैबिनेट से मंजूरी के बाद राशि संबंधित प्राधिकरणों को जारी कर दी जाएगी। इसके बाद टाउनशिप योजना आगे बढ़ सकेगी। >> सबसे ज्यादा धन गोरखपुर को : पेज 2